मूल्य 1 रुपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 67 | सितम्बर, 2022 | अंक 09 | कुल पृष्ठ 8

हर सामाजिक कार्यकर्ता को पढ़नी चाहिए 'आंदोलनजीवी'

विनोद अग्निहोत्री
लेखक और पत्रकार

हाल ही में पाखी प्रकाशन द्वारा छापी गई किताब आंदोलनजीवी भारत के किसान आंदोलनों और कुछ अन्य जन आंदोलनों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें 2020-21 में दिल्ली में हुए किसान आंदोलन का संदर्भ लेते हुए उन तमाम किसान आंदोलनों का सिलसिलेवार जिक्र है जो मैने अपने 37 सालों की पत्रकारिता के दौरान न सिर्फ उन्हें कवर किया बल्कि उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संवाद करके उन आंदोलनों के भीतर चलने वाली राजनीति और बाहर भीतर के दबावों को भी बेहद करीब से देखा है।मेरी इस किताब का साठ से सत्तर फीसदी हिस्सा देश के किसान आंदोलनों की पृष्ठभूमि, आजादी से पहले के किसान आंदोलनों का जिक्र और आजादी के बाद किसान राजनीति और सत्तर अस्सी के दशक में होने वाले उन किसान आंदोलनों पर केंद्रित है जिनका नेतृत्व उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह टिकैत, महाराष्ट्र में शरद जोशी, विजय जावंधिया, कर्नाटक में डा.नंजदुम्मा स्वामी, बाबा गौड़ा पाटिल, गुजरात में विपिन भाई देसाई, पंजाब में भूपेंद्र सिहं मान, अजमेर सिंह लाखोंवाल, हरियाणा में घासीराम नैन, प्रेम सिंह दहिया, मध्य प्रदेश में सुनील और डा.सुनीलम ने किया। इनके अलावा किताब में छत्तीसगढ में शंकर गुहा नियोगी की अगुआई में चले खदान मजदूरों और आदिवासी किसानों के रचनात्मक आंदोलन, स्वामी अग्निवेश और कैलाश सत्यार्थी के बंधुआ और बाल बंधुआ मजदूर मुक्ति आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी

के चिपको आंदोलन, शमशेर सिंह बिष्ट पीसी तिवारी, शेखर पाठक राजीव लोचन शाह के नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन और उत्तराखंड राज्य आंदोलन, प.बंगाल के नक्सलवादी आंदोलन, कांशीराम मायावती के बहुजन आंदोलन और 2012 में दिल्ली में हुए अण्णा आंदोलन पर भी लिखा गया है। यह किताब इन सारे आंदोलनों पर एक तरह से मेरी पत्रकारीय यात्रा का रिपोर्ताज नुमा दस्तावेज है।

इस किताब के शीर्षक से लोगों को यह भ्रम हो सकता है कि शायद मैने यह किताब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली के किसान आंदोलनकारियों के लिए प्रयोग किए गए आंदोलनजीवी शब्द की प्रतिक्रिया या समर्थन में लिखी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस किताब की योजना कई वर्ष पहले ही बन गई थी और मैने लिखना भी शुरु कर दिया था। लेकिन व्यस्तता के कारण किताब लिखने का काम बीच में ही छूट गया। लेकिन जब दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ तो उसका संदर्भ लेकर मैने अपनी किताब पूरी की और इसका शीर्षक एक किसान नेता आत्मजीत सिंह के सुझाव पर मैने आंदोलनजीवी रखा।इसका प्रधानमंत्री के बयान से कोई लेना देना नहीं है।

आंदोलनजीवी के पहले अध्याय में मैने उन सपनों जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे सेनानियों ने देखे और जनता को दिखाए, उनके बिखरने और टूटने का जिक्र करते हुए आजादी के बाद देश में हुए तमाम जन आंदोलनों और राजनीतिक बदलावों का जिक्र किया है। इसमें जवाहर लाल नेहरू के राष्ट्र निर्माण, इंदिरा गांधी की सशक्त नीतियों और उनके समानांतर राम मनोहर लोहिया, वाम दलों और जय प्रकाश नारायण के लोकतंत्र बचाओ आंदोलन, दाम बांधो, सिंचाई और किसानों के मुद्दों पर किए जाने वाले आंदोलनों का जिक्र है। किताब के एक अन्य अध्याय में किसान राजनीति को किसान आंदोलन से अलग रूप में रखा गया है। आजादी के पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती और बाबा रामचंदर और अखिल भारतीय किसान महासभा की अगुआई में जहां किसानों के मुद्दे पर आंदोलन हुए वहां तत्कालीन पंजाब में बतौर राजस्व मंत्री सर छोटूराम ने मंडी कानून बना कर किसानों को जिस तरह आढ़तियों और महाजनों के चंगुल से मुक्त करने का रास्ता खोला, उसने देश में किसान राजनीति को आगे बढ़ाया। जिसके सबसे बड़े पैरोकार उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह बने जिन्होंने सहकारी कृषि के नेहरू के प्रस्ताव पर कांग्रेस से अलग होकर किसानों का दल बनाया और संविद सरकार में मुख्यमंत्री बने। चरण सिंह की अगुआई में देश की राजनीति में गांव खेत खलिहान और किसानों के मुद्दे काफी प्रमुख हो गए। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब,

मध्य प्रदेश बिहार उड़ीसा कर्नाटक, महाराष्ट्र गुजरात तमिलनाडु आंध्र प्रदेश जैसे खेती प्रधान राज्यों में कई ऐसे नेता राजनीति में आगे आए जिनकी पृष्ठभूमि खेती किसानी वाली थी। देवीलाल, नाथूराम मिर्धा, रामनिवास मिर्धा, वीरेंद्र वर्मा, बलराम जाखड़, कुंभाराम आर्य, दौलतराम सारण, शीशराम ओला, वसंत दादा पाटिल, शरद पवार, पंजाब राव देशमुख, प्रकाश सिंह बादल, रामसेवक यादव, महादेव वर्मा, मुलायम सिंह यादव, रामलखन यादव सत्यपाल मलिक राजेश पायलट, रामचंद्र विकल जैसे कई नेताओं के नाम गिनाए जा सकते हैं। किताब में इसका भी विस्तार से जिक्र है।

आंदोलनजीवी में यह स्पष्ट किया गया है कि जब तक देश में सभी राजनीतिक दलों में किसानों की बात करने वाले नेताओं का वर्चस्व रहा किसानों को सड़क पर उतर कर आंदोलन करने की जरूरत बहुत कम ही पड़ी। लेकिन जैसे जैसे राजनीति में कार्पोरेट जगत का दबदबा बढ़ा और किसान नेता अपनी तिकड़मों और आपसी झगड़ों में उलझकर प्रभावहीन होते गए किसानों को अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र रूप से गैर राजनीतिक किसान संगठनों के रूप में संगठित होना पड़ा। इस तरह का पहला प्रयोग दिल्ली में 1980 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में कंझावला गांव में गोचर जमीन का आवंटन भूमिहीन दलितों को किए जाने के आदेश के खिलाफ किसानों की गोलबंदी से शुरु हुआ और यहीं से पहली बार भारतीय किसान यूनियन नामक किसान संगठन की स्थापना हुआ।यह वह दौर था जब चरण सिंह की राजनीतिक रूप से कमजोर हो रहे थे और उनकी सेहत ने भी उनकी सक्रियता कम कर दी थी। इसी दौर में महाराष्ट्र में विश्व बैंक की नौकरी छोड़कर आए शरद जोशी और किसानों के बीच काम कर रहे विजय जावंधिया ने प्याज और गन्ने की कीमतों को लेकर किसानों को संगठित करने के लिए शेतकारी संगठन बनाया जो जल्दी ही पूरे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा किसान संगठन बन गया। कर्नाटक में डा. नंजदुम्मा स्वामी की अगुआई में किसानों का सबसे बड़ा संगठन बना। उत्तर भारत में कंझावला आंदोलन की आग जल्दी ही हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में फैल गई और जगह जगह भारतीय किसान यूनियन के नाम से कई किसान संगठन बन गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश डा. सत्येंद्र और रणसिंह आर्य जैसे नौजवानों ने वालियान खाप के चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को आगे करके भारतीय किसान यूनियन का गठन किया। मुजफ्फरनगर जिले के कर्मूखेड़ी बिजली घर के घेराव से शुरु हुआ यह आंदोलन जल्दी ही पूरे देश में चर्चित हो गया। टिकैत के नेतृत्व में मेरठ, दिल्ली, भोपा, मुरादाबाद आदि के किसानों के लंबे और बड़े धरनों ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार

को किसानों के सामने झुकने को मजबूर कर दिया।

किताब में इन सारे आंदोलनों का विस्तार से जिक्र करते हुए मैने अपने उन तमाम अनुभवों को भी साझा किया है जो इस दौरान मुझे मिले। कई ऐसी घटनाओं का भी उल्लेख है जिनका जिक्र पहले कभी किसी अखबार या मीडिया के किसी हिस्से में नहीं हुआ।किताब में जिक्र है कि किसानों के धरनों और आंदोलनों का कैसे राजनीतिक दलों और उनके दिग्गज नेताओं ने अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया और किसान अनजाने में उनके हाथों में खेलते रहे।उदाहरण के लिए जब भारतीय किसान यूनियन ने पहली बार दिल्ली के बोट क्लब पर धरना दिया और केंद्र सरकार के सामने लंबा चौड़ा मांग पत्र पेश किया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी किसानों की कई मांगों को हल करने के पक्ष में थे, लेकिन कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं ने अपने संपर्क सूत्रों के जरिए महेंद्र सिंह टिकैत को मना लिया और भारतीय किसान यूनियन की कार्यकारिणी से बिना बात किए टिकैत ने अचानक धरना उठाने की घोषणा कर दी।इससे नाराज कार्यकारिणी के सदस्य उन युवा किसानों ने जो तब तक भारतीय किसान यूनियन के कर्ता धर्ता थे, टिकैत की मनमानी के खिलाफ बुलंदशहर के सैदपुर में समानांतर किसान पंचायत बुलाई। लेकिन यह पंचायत विफल हो गई और इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन पर पूरी तरह टिकैत उनके सलाहकारों और परिवार का कब्जा हो गया जो अब भी बरकरार है।

किताब में मैने उस प्रक्रिया का भी विस्तार से जिक्र किया है कि कैसे जल्दी ही टिकैत और अन्य किसान नेताओं के बीच वाद संवाद शुरु हुआ और दो अक्टूबर 1989 को देश भर के किसान संगठनों की एक विशाल रैली दिल्ली के बोट क्लब पर आहूत हुई। लेकिन किसान नेताओं के अहंकार और टकराव ने इस रैली को टिकैत बनाम जोशी की लड़ाई में बदल दिया और एक राष्ट्रीय किसान आंदोलन की संभावनाएं पूरी तरह खत्म हो गई।

किताब में मेरा विश्लेषण है कि मंडल और कमंडल (मंदिर) राजनीति ने भी किसान आंदोलन और किसान संगठनों को भारी नुकसान पहुंचाया। अपने को राजनीति से दूर रखने का दावा करने वाले कई किसान नेता धीरे धीरे राजनीतिक दलों के करीब होते गए और इनमें शरद जोशी भूपेंद्र सिंह मान तो राज्यसभा में चले गए जबकि बाबा गौड़ा पाटिल तो वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बने।कई मझोले किसान नेता और कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने इलाके के प्रभावशाली दलों में जाकर विधायक और सांसद का चुनाव लड़ा। कुछ जीते तो कुछ हारे। यहां तक कि महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे

राकेश टिकैत ने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन वह हार गए। मंडल मंदिर की राजनीति ने किसानों खासकर उत्तर प्रदेश बिहार हरियाणा मध्य प्रदेश राजस्थान जैसे राज्यों में जाति और धर्म में बांट दिया। किसानों के नेता जातियों के नेता हो गए और गन्ना कपास और प्याज के दामों की लड़ाई भूल कर किसान अयोध्या के राम मंदिर के लिए ईंटे जुटाने में जुट गए। अपनी पहली गिरफ्तारी के बाद वाराणसी जेल में मिलने गए भाजपा नेता कल्याण सिंह से खुश होकर महेंद्र सिंह टिकैत ने 1991 के विधानसभा चुनावों में किसानों से राम का नाम लेकर वोट डालने की अपील कर दी, जो सीधे सीधे भाजपा के पक्ष में जाती थी।

किसान आंदोलन और किसान नेताओं के इस उत्थान पतन की दास्तान को समेटे मेरी किताब में यह बताने का प्रयास किया गया है कि दिल्ली में करीब एक साल तक चले किसानों के ऐतिहासिक धरने की जड़ें दरअसल अस्सी के दशक में देश में शुरु हुए किसान आंदोलन में हैं और जिन मुद्दों को लेकर तब किसानों ने आंदोलन किया था, आज भी वही मुद्दे उसी तरह से किसानों के बीच सुलग रहे हैं। इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी, कृषि उपज का लाभकारी मूल्य जो लागत से कम से कम डेढ से दो गुना हो। बिजली, खाद, डीजल, बीज के दामों पर नियंत्रण, कर्ज के जाल से किसानों की मुक्ति, कृषि उपज को बेचने की पूरी छूट और प्राकृतिक आपदा में किसान को नष्ट फसल का पर्याप्त मुआवाजा जैसे मुद्दे आज भी किसान आंदोलन के प्रमुख एजेंडे हैं।

किताब में जिन आंदोलनों का जिक्र है, वो सब अब या तो बिखर गए हैं या उनका अस्तित्व बेहद सीमित हो गया है। किसान आंदोलन के बिखरने का विस्तार से वर्णन तो है ही, इसके अलावा नक्सलवादी आंदोलन अब एक हिंसक उग्रवादी माओवादी लड़ाई में बदल गया है जो भारतीय राज्य और लोकतंत्र के लिए एक आंतरिक चुनौती है। शंकर गुहा नियोगी की हत्या के बाद छत्तीसगढ़ का मजदूर किसान आंदोलन अब बेहद सीमित दायरे में है।एके राय, विनयन, दत्ता सामंत के आंदोलन भी दम तोड़ चुके हैं। कांशीराम का बहुजन आंदोलन बसपा और मायावती की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ गया। यही हश्र अन्ना आंदोलन का हुआ जिसके गर्भ से निकलकर देश को नई राजनीतिक देने का दावा करने वाली अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी दूसरे दलों की तरह विशुद्ध सत्ता की राजनीति में उलझ गई।स्वामी अग्निवेश और कैलाश सत्यार्थी के रास्ते अलग अलग हो गए। जहां सांप्रदायिक ताकतों से लड़ते हुए स्वामी अग्निवेश हमले का शिकार हुए और आखिरकार लंबी बीमारी के बाद उनकी मौत हो गई। कैलाश सत्यार्थी को

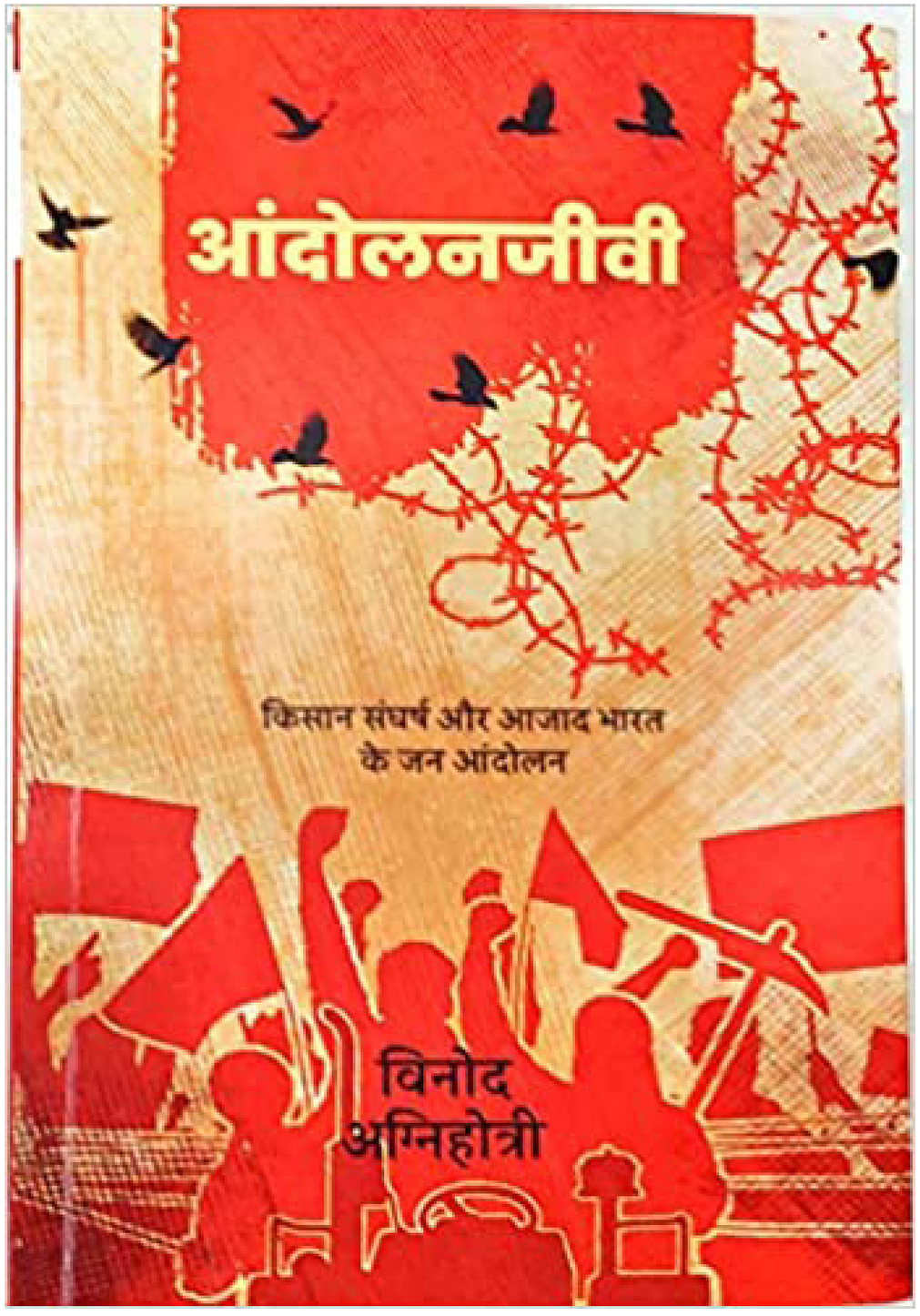

नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उनकी प्राथमिकताएं अब वैश्विक हो गई हैं। मेधा पाटकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध बनने के साथ ही समाप्त हो गया, लेकिन मेधा अभी भी विस्थापन और मानवाधिकारों के सवालों पर सक्रिय हैं। उत्तराखंड के चिपको और नशा नहीं रोजगार दो आंदोलनों द्वारा तैयार जमीन पर अलग राज्य उत्तराखंड का निर्माण तो हो गया लेकिन इन दोनों आंदोलनों के मुद्दे अब इस पर्वतीय राज्य में गौण हो गए हैं।

आंदोलनों की इन सफलताओं और विफलताओं का विवेचन करते हुए आंदोलनजीवी का निष्कर्ष है कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज में आंदोलन और उसकी चेतना कभी खत्म नहीं होती और न ही होनी चाहिए। डा. राममनोहर लोहिया का यह कथन कि अगर सड़कें सूनी हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी इसी संदर्भ में कहा गया कि जनता को सत्ता की मनमानी और अपने सवालों को लेकर हमेशा मुखर रहना चाहिए। यही लोकतंत्र की संजीवनी भी है और ताकत भी। इसलिए किताब में इस उम्मीद के साथ कानपुर के मशहूर मजदूर नेता स्वर्गीय कामरेड रामआसरे के कथन को अंतिम पैरा में उद्धृत किया गया है कि इस दुनिया में दो दुनिया हैं। एक कमाने वाले की एक लूटने वाले की। जब तक यह दोनों दुनिया हैं इनका संघर्ष जारी रहेगा। 17 अगस्त 2022 को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भाजपा के वरिष्ठ नेता डा.मुरली मनोहर जोशी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी, जनता दल(यू) के प्रधान महासचिव के.सी.त्यागी, वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता ने आंदोलनजीवी पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के संगठन की बुनियाद रहे डा.सत्येंद्र और डा.रणसिंह आर्य को सम्मानित भी किया गया और उनके संस्मरण भी सुने गए। यह किताब ऑनलाईन अमेजन पर आर्डर देकर मंगाई जा सकती है।

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

RNI No. 831/1957 **प्रकाशन की तिथि : 1 सितम्बर, 2022**
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2021-23 **एल.पी.सी., दिल्ली आर.एम.एस, दिल्ली–6,**
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं. U(C)-92/2021-23 **तारीख 4 एवं 5, सितम्बर 2022**

सार्वजनिक सूचना

भारत कृषक समाज के सदस्यों से अनुरोध है कि वे भारत कृषक समाज के महासचिव के कार्यालय के साथ अपने संपर्क विवरण को अद्यतन करें।

संपर्क विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है:

नामः _____

सदस्यता संख्याः _____

वर्तमान पताः _____

_____

टेलीफोन नंबरः _____

मोबाइल नंबरः _____

ईमेलः _____

(कृपया पते का सबूत की एक छायाप्रति संलग्न करें)

विधिवत भरा हुआ फॉर्म निम्नलिखित पते पर स्पीड पोस्ट या ईमेल द्वारा इस माह के अन्त तक या उससे पहले जमा कराएं:

महासचिव
भारत कृषक समाज
ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली, 110013
ईमेलः– Samdarshi.bks@gmail.com
टेलीफोनः– 011–41402278

नोटः आपसे अनुरोध है कि आप अन्य सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए सूचित करे।

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–41402278, 9667673186, ई–मेलः ho@bks.org.in, **वैबसाईटः** www.bks.org.in **के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।**